POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–9 SEPT 2024 AMBERNATH PAGE 1 OF 4 RS 5/-

न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तथा मीडिया का लेखा-जोखा जनता तक पहुंचाना , प्रारंभ मे एक मासिक के रूप में शुरू, इस मासिक समाचार पत्र का मूल उद्देश्य है । पाठक अपना विचार हिन्दी या अंग्रेजी में बेहिचक दे सकते हैं । शर्त सिर्फ यह है कि विचार किसी भी तरह के , प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से,पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए ।

email id: vote1957@gmail.com

कोलकाता में बलात्कार के बाद डॉक्टर की हत्या

कोलकाता के एक बड़े हॉस्पिटल में यह शर्मनाक घटना घटी है।देश में अपराधियों के मन से अपराध करने में नाममात्र भी डर नहीं दिखता है। इसके पहले कि अपराध और अपराधी बेकाबू हो जाए , पश्चिम बंगाल की सरकार को विशेष ध्यान देकर कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखना चाहिए।इस तरह की घटनाएं बीजेपी द्वारा पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के बिगड़ने की बात को बल मिलता है।

बिहार के मुजफरपुर में सामूहिक बलात्कार के बाद नाबालिग दलित बच्ची की हत्या

बिहार भी पीछे क्यों रहे ! चंद दिनों के दरम्यान यहां बलात्कार तथा हत्या की दो वारदात घट चुकी है। इसके पहले बिहार के मधुबनी जिला में तरह से एक बच्ची की बलात्कार तथा हत्या हुई है।सरकारों का तकिया कलाम चालू हो जाता है जैसे :- "दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा तथा सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी, कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है।"

अब ये उत्तराखंड में एक नर्स के साथ ब्लातकार कर उसकी हत्या की गई

बंगाल, बिहार, , और अब उत्तराखंड !

और ये सब आजादी के अमृतकाल में हो रहा है।

एक दूसरे को दोष देने के बजाय सभी सरकारें , सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर अपराध मुक्त भारत के लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाती हैं ! पुलिस, जांच तथा न्याय व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त किए बिना क्या ऐसा संभव है।

जांच में महीनों लगते हैं, ट्रायल में वर्षों लगते हैं। अपील, रिव्यू तथा रिवीजन में दशकों लग जाते हैं। तबतक जेल में या जमानत पे मौज करता है।

राजनीतिक पार्टियों को भी अपराधियों से मुक्त करने की जरूरत है।

आरक्षण के लिए एससी/एसटी के अंदर भी वर्गीकरण हो सकता है - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का 6:1 के बहुमत से दिया गया ये फैसला का व्यावहारिक असर ये हो सकता है कि अब आरक्षण के अंदर भी आरक्षण संभव है।

फैसले में ये भी कहा गया है कि आरक्षणों में क्रीमी लेयर के लोगों को आरक्षण से बाहर करना चाहीए।

मिडल ईस्ट में भी संकट के बादल

ईरान में हमास नेता का मारा जाना तथा ईरान द्वारा इसराइल के खिलाफ बदले की कार्रवाई की चेतावनी से इस क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया है।ज्ञातव्य है कि फिलिस्तीन के हमास द्वारा इसराइलियों की नृशंस हत्या तथा कई इसराइलियों को बंधक बनाने की घटना से क्षुब्ध तथा क्रुद्ध इसराइली सेना द्वारा प्रतिकारात्मक कार्रवाई में अबतक हजारों फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है।

सारी दुनिया स्तब्ध है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हिंसा पर रोक का आग्रह कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी चिंता व्यक्त कर चुका है। पर इसराइल पर कोई असर नहीं दिखता है।

अब ये ईरान की भूमि पर हमास नेता का मारे जाने की घटना को ईरान गंभीरता से लिया लगता है।विश्व के प्रभावकारी शक्तियों को विश्व को शांति तथा अहिंसा का स्थान बनाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए

Epidemic Of Rape - A Shame For India
Figures For 2022, Courtesy NCRB, GOI

	State/UT	Murder with Rape/Gang Rape			Rape (Total)		
		Incident	Victim	Rate	Incidents	Victim	Rate
	States						
1	Andhra Pradesh	8	8	0	621	627	2.3
2	Arunachal Pradesh	0	0	0	74	74	9.8
3	Assam	14	14	0.1	1113	1478	6.4
4	Bihar	9	0	0	881	881	1.5
5	Chhattisgarh	7	7	0	1246	1246	8.3
6	Goa	1	1	0.1	73	75	9.4
7	Gujarat	12	12	0	610	610	1.8
8	Haryana	8	8	0.1	1787	1787	13
9	Himachal Pradesh	2	2	0.1	359	369	9.8
10	Jharkhand	7	7	0	1298	1298	6.8
11	Karnataka	8	8	0	595	598	1.8
12	Kerala	2	2	0	814	820	4.4
13	Madhya Pradesh	41	43	0.1	3029	3046	7.3
14	Maharashtra	22	22	0	2904	2911	4.8
15	Manipur	0	0	0	42	42	2.6
16	Meghalaya	1	1	0.1	75	75	4.5
17	Mizoram	0	0	0	14	14	2.3
18	Nagaland	0	0	0	7	7	0.7
19	Odisha	14	14	0.1	1464	1464	6.4
20	Punjab	3	3	0	517	517	3.6
21	Rajasthan	9	9	0	5399	5408	14
22	Sikkim	0	0	0	13	13	4
23	Tamil Nadu	6	6	0	421	421	1.1
24	Telangana	7	7	0	814	814	4.3
25	Tripura	5	5	0.2	62	62	3.1
26	Uttar	62	62	0.1	3690	3692	3.3
27	Uttarakhand	1	1	0	867	905	15
28	West Bengal	5	5	0	1111	1112	2.3
	TOTAL	245	247	0	29900	30366	4.6
	UNION TERRITORIES:						
29	A&N Islands	1	1	0.5	12	12	6.3
30	Chandigarh	0	0	0	78	78	14
31	D&N Haveli and Daman & Diu	2	2	0.5	9	9	2.2
32	Delhi	0	0	0	1212	1212	12
33	Jammu & Kashmir	0	0	0	287	287	4.5
34	Ladakh	0	0	0	5	5	3.8
35	Lakshadwee	0	0	0	4	4	12
36	Puducherry	0	0	0	9	9	1.1
	TOTAL UT(S)	3	3	0	1616	1616	8.7
	TOTAL ALL INDIA	248	250	0	31516	31982	4.7

OPS, NPS And Now UPS

This govt is known for making a mess and confusion for everything . Hardly it has done anything which has gone unchallenged and without criticism..

What is the necessity for the name change as UPS when there is already OPS and NPS. If it was really interested to address the concern of its employees - it could have simply provided an option for choosing OPS or NPS.

Rate of family pension has been differently worded in this UPS which says that family pension shall be 60% of the pension which is same as the 30% of the last pay drawn by the pensioners of the OPS.

This is nothing but creating confusion like Old Tax Regime and New Tax Regime wherein people have no option other than opting for the New Tax Regime after a certain income limit.

नोबेल विजेता मुहम्मद युनुस ने बांग्लादेश का अंतरिम कमान संभाला !

भारत के प्रधानमंत्री नटेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए बांग्लादेश में शीघ्रातिशीघ्र शांति बहाल करने तथा वहां हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की अपील की है।

बांग्लादेश में सही माने में लोकतंत्र बहाल हो - ये हम सबकी की कामना है !

दुनिया का खेल निराला

मात्र 100 ग्राम शरीर का वजन ज्यादा पाए जाने के कारण पहलवान विनेश फोगाट को अंतराष्ट्रीय ओलंपिक से आउट कर दिया गया !ये कैसा नियम है ! नियम का तर्क (logic), औचित्य तथा अनिवार्यता क्या है !

सेमीफाइनल तक ठीक फाइनल में अयोग्य !

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी को विचार करना चाहिए !

ये नरसंहार नहीं तो क्या है !

धरती पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसराइल द्वारा फिलिस्तीन में, रूस और यूक्रेन के टकराव में, बंगलादेश में आंदोलनकारियों के दमन में , किसी न किसी बहाने आदमी आदमी की जान ले रहा है।म्यांमार में भी कुछ वर्ष पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हटा कर वहां की मिलिट्री ने कब्जा कर रखा है। इनके विरोध में भी सशस्त्र ग्रुप हैं। इन्ही में एक है अराकान आर्मी ।म्यांमार के पश्चिमी राज्य रखाइन में इस सप्ताह तोपखाने और ड्रोन हमले में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक नागरिक मारे गए हैं।

POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–9 SEPT 2024 AMBERNATH PAGE 2 OF 4 RS 5/-

नलिनी चिदंबरम के खिलाफ ईडी का मामला खारिज

सीनियर एडवोकेट नलिनी चिदंबरम (जो कांग्रेस नेता तथा पूर्व वित्त तथा गृह मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी हैं) खिलाफ ईडी ने पश्चिम बंगाल के सारधा चिटफंड घोटाला से जोड़ कर मनी लॉन्ड्री का मामला दर्ज किया था।

कोलकाता के एक मनी लॉन्ड्री कोर्ट के जज प्रशांत मुखोपाध्याय ने उक्त मामले को खारिज (dismiss) कर दिया ये कहते हुए कि उक्त मामला मनी लौंडी के कानून (PMLA) में बनता ही नहीं है।

ज्ञातव्य है कि नलिनी चिदंबरम को पश्चिम बंगाल के एक फर्म सारधा रियल्टी इंडिया लिमिटेड को वकीली सलाह देने के लिए मिलने वाले एडवोकेट फीस को मनी लॉन्ड्री से जोड़ दिया था।

अब अपीलों का दौर शुरू होगा। मामला ऊपरी अदालतों हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है ।

सरकार मेरे खिलाफ ईडी लगाने की योजना बना रही है - राहुल गांधी, लोकसभा/राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव

जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर तथा गृहमंत्री के तथाकथित बयान पर कि वायनाड के प्राकृतिक दुर्घटना की सूचना केरल सरकार को पहले ही fi गई थी।

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट/X पर बताया है कि उन्हें जनकातीली है कि सरकार उनके पीछे ईडी लगा रही है। उनके मुताबिक ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने लोकसभा के बजट सत्र में अपने भाषण में चक्रव्यूह की चर्चा की थी।

लगता है कि विपक्ष दोनों ही मुद्दों पर सरकार को संसद के दोनों सदनों में घेरने जा रहा है। मतलब संसद में हमेशा की तरह शोरगुल का आलम रहेगा !

ये कैसा न्याय है, भाई !

गुप्त चुनाव बॉन्ड के लाभुकों की जांच एसआईटी से नहीं कराएगा सुप्रीम कोर्ट

इस बॉन्ड स्कीम के लाभार्थियों द्वारा प्राप्त धन की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी से कराए जाने की मांग वाली लोकहित याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सामान्य प्रक्रियाओं का सहारा लिया जा सकता है जैसे एफआईआर, निचली अदालत, हाईकोर्ट आदि।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अरबों खरबों में लेनदेन वाले इस गुप्त बॉन्ड स्कीम से अर्जित धन की जांच से सुप्रीम कोर्ट का इंकार किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

और ये भी तब जब :-

1. स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ही इस स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त किया था।

2. स्वयं सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लेन देन करने वाले लाभुक पार्टियों तथा दान दाताओं के नाम वाली लिस्ट जारी किया था।

लेन देन में जांच एजेंसियों के प्रभाव का भी जिक्र किया गया था याचिकाओं में।

ऐसे में क्या इन जांच एजेंसियों से इन वित्तीय अनियमितताओं यानी रिश्वतखोरी की की जांच न्यायपरक जांच की अपेक्षा करना संभव है !

देर सवेर सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना ही पड़ेगा।

वैसे सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बावजूद पेगासस प्रकरण, हिंडेनबर्ग प्रकरण के बारे में परिणाम कहां नजर आ रहा है

Caste or Religion of Persons of Intercaste or Inter-religion marriages

Calling of castes in parliament has given rise to a new debate as to which caste or religion the couples of such marriages can have. Some says that it is paternity that decides one's caste or religion. I hold the view as under :-

This myth too needs to be bulldozed that castes or religions are inherited from paternity. The male dominated society must have laid this so-called rule or tradition.

In fact these must be optional. Despite her marriage with Pheroz Gandhi Smt Indira Gandhi continued her faith in Hinduism which she had right to.

The fundamental right under Article 25(1) gives one a right to have religion of his choice. This includes freedom to not profess any religion or become atheist etc.

Here is what the article says:-

Article 25, Constitution of India 1950

(1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.

So where is the question for justification of his or her religion .

Couples undergoing intercaste or inter religious marriages can have caste or religion of their choices and so have their offsprings after they obtain adulthood ie the age of majority. As such minors should be exempted from going through the rigours of castes or religions !

गुजरात के पुलिस इंस्पेक्टर तथा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को सुप्रीम कोर्ट दंडित करेगा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने के बावजूद गुजरात के सूरत के एक पुलिस इंस्पेक्टर ने अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में ली वहां के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट से - यह जानते हुए कि अभियुक्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) मिला हुआ है। अभियुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना (Contempt Of Court) की एसएलपी दायर किया था।

सुनवाई के दौरान पुलिस तथा मजिस्ट्रेट के द्वारा ये दलील दी गई है कि गुकरात में ऐसा चलन है कि जमानत के दौरान भी पुलिस किसी को अपने हिरासत में ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य किया तथा इंस्पेक्टर तथा जज महोदय दोनो को ही कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया है तथा दोनों को सुप्रीम कोर्ट में 2 सितंबर को सजा सुनने के लिए बुलाया है।

जस्टिस बी आर गवई तथा जस्टिस संदीप मेहता के सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने गुजरात के इस चलन पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए इसे गलत बताया है तथा इसे आर्टिकल 21 का हनन बताया है।

मनीष सिसोदिया के बाद अब बीआरएस की नेता के कविता को भी जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने !

सुप्रीम कोर्ट का तेंवर मनीष सिसोदिया के मामले जैसा ही था। जजों के कुछ रिमार्क्स:-1. 493 गवाह

2. 50000 पृष्ठों के भारी भरकम दस्तावेज

3. इसलिए ट्रायल को पूरा नजदीक भविष्य में पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं है।

4. बड़े अपराधों के दोषियों को ही सरकारी गवाह बनाकर चुनिंदे दोषियों को मोहरा बनाना उचित नहीं है।

5. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को चेतावनी कि अगर वे बेल का विरोध मेरिट पर करेंगे तो बेल ऑर्डर में ये सब बातें भी लिखनी पड़ेंगी। इस पर एएसजी का कोर्ट की बात मान लेना और चुप बैठ जाना।

6. निचली अदालतों द्वारा इस आधार पर कि अभियुक्त बहुत सुशिक्षित पढ़ीलिखी तथा एक एमपी एमएलए है जमानत के इनकार किए जाने की भी सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है।

POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–9 SEPT 2024 AMBERNATH PAGE 3 OF 4 RS 5/-

Does Reservation Policy Need A Relook !

Rahul Gandhi or for that matter the India Alliance have played the same game as was played by V P Singh for Mandal Commission. This is proving very difficult for BJP and its NDA partners to nullify its effects as far as vote banks are concerned.

Congress slogan of reservation in the ratio of population (जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी /हिस्सेदारी) invited mixed reactions and those who consider themselves to be following small family norms didn't take the slogan kindly .

The recent Supreme Court judgment on reservation has tried to regulate the reservation like creating sub castes within the castes and also introduction of creamy layers concept to exclude the persons within the creamy layers from the purview of reservation.

My considered view on reservation is that the truly deserving and deprived sections of our society must be uplifted and brought in the mainstream by whatever means including the most important tool of reservation.

However It should not be stretched so much so as to bring within its purview the well off classes which have long been craving to have reservation like Meena or Gujars in Rajsthan or Marathas in Maharashtra . This will open pandora box.

Free for all can open the pandora's box which can go against the most important and indispensable right of Equality as enshrined under Article 14 of our Constitution.

Today virtually all castes have been brought within the purview of reservation with introduction of 10% reservation for EWS among forward castes.

We should also see that merits or efficiencies are not compromised as mentioned in article 335 of our Constitution which I am reproducing below:-

335. The claims of the member of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently, with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State.

335. The claims of the member of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently, with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State.

Buddhadeb Bhattacharjee Is No More !

The Great Communist leader and former Chief Minister, Buddhadeb Bhattacharjee passed away today morning at 80 years of his age. He had been ailing for quite some time.

He is known more for his bold steps for industrialisation in West Bengal , particularly the Tata Nano project at Singur and Nandigram. Mamata Bannerjee then a TMC leader launched agitation against the move and succeeded in stalling the projects which were consequently shifted elsewhere.

He is also known for his simplicity and simple lifestyle.

My heartfelt condolence to his bereaved family members and heartiest tribute to the great leader !

हिंडेनबर्ग है कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है

ज्ञातव्य है कि पिछले साल दुनिया में तहलका मच गया था हिंडेनबर्ग के इस खुलासे से कि अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेराफेरी कर के अपने शेयरों के भाव बढ़ा दिए थे। भारत में भी हो हंगामा हुआ था। संसद ठप्प किया गया था। जेपीसी द्वारा जांच की मांग कर रहा था विपक्ष।

सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए थे पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ही जांच का काम दे दिया था। सेबी ने रिपोर्ट दिया था कि सब कुछ ठीक ठाक है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था। विपक्ष भी शांत हो गया था भले ही भारी मन से !

अब हिंडेनबर्ग ने फिर एक खुलासा कर के उस मामले को फिर से ताजा कर दिया है।

खुलासा ये है कि सेबी प्रमुख स्वयं तथाकथित शेयरों के हेराफेरी के लाभार्थी हैं क्योंकि उनके भी शेयर हैं अडानी के फर्मों में।

अंतत: मनीष सिसोदिया को जमानत मिली !

जस्टिस बी आर गवई तथा जस्टिस के वी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने न्याय दिया :-

1. मामले के निपटान में हो रहे विलंब के लिए मनीष सिसोदिया जिम्मेवार नहीं हैं।

2. सीबीआई/ईडी के स्टैंड में विरोधाभास है। एक तरफ ये कहती हैं कि न्याय प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और दूसरी तरफ किसी न किसी बहाने तारीख पर तारीख मांगती हैं।

3. मामले को फिर से ट्रायल कोर्ट ने भेजना सांप सीढी का खेल में आरोपियों को उलझाना है।

4. नीति निर्धारण तथा अपराध में फर्क करना चाहिए। सिर्फ इस लिए कि किसी नीतिगत फैसले से किसी को लाभ हुआ किसी को अपराधी कैसे करार दिया जा सकता है

5. नाम मात्र भी उम्मीद नहीं दिखती है कि ट्रायल नजदीक भविष्य में पूरा होगा।

6.17 महीनों से जेल में रखना तथा ट्रायल का शुरू भी नहीं होना स्पष्ट रूप से शीघ्र ट्रायल के अधिकार (Right to Speedy trial) का उल्लंघन है। ये आर्टिकल 21 में प्रदत मूलभूत अधिकार वैयक्तिक स्वतंत्रता का हनन है।

7. मनीष सिसोदिया की समाज में गहरी पैठ है। उनके भागने (Flight risk) की संभावना नहीं है।

8. इस मामले में करीब करीब सारे सबूत दस्तावेजी हैं जिन्हे इकट्ठा किया जा चुका है। इसलिए इन दस्तावेजों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की भी संभावना नहीं है।

9. गवाहों को डराने धमकाने की संभावना के लिए जनाबत में शर्ते डाली जा सकती हैं।

10. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी पक्ष की मांग को ठुकरा दिया कि इनकी जमानत में भी अरविंद केजरीवाल जैसा शर्त रखा जाय कि वे मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में नहीं जा सकते हैं।

11. ट्रायल कोर्ट्स तथा हाई कोर्ट्स विधिशास्त्र के इस नियम को भूलते जा रहे हैं कि " बेल नियम है जेल अपवाद"(Bail is the rule, jail is exception). All play safe and send the accused to jail. Without trial putting some one in jail should not become a kind of punishment.

ये सही है कि जमानत मिलना निर्दोष होने का प्रमाण नहीं है पर जेल से मुक्ति मिलना , तिस पर जांच एजेंसियों के प्रति कोर्ट की ऐसी तीखी टिप्पणी आरोपियों के मन में दिलासा तो जरूर पैदा करता है।

Protest Turns Violent

BJP's Sponsored Or Supported protest in the aftermath of the heinous and brutal rape and murder of a Kolkata's Doctor has fast turned into a ploy to take on and demand for resignation of Mamata Banerjee !

So Called Peaceful Protest Turns Violent so much so that a police official in Kolkata loses vision of his one eye !

विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उपेक्षा

लाल किला के स्वतंत्रता समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नियमों (प्रोटोकॉल) की अनदेखी करते हुए उन्हें सबसे पीछे की कतार में जगह दी गई जबकि विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा हासिल होने के चलते उन्हें सबसे आगे की कतार में बिठाना चाहिए था।

राहुल गांधी ने आजादी के समारोह का कद्र करते हुए कोई आपत्ति नहीं दिखाई वरना उनकी जगह कोई और होता था वहां से बाहर आकर अपना विरोध दर्ज जरूर कराता।

बीजेपी सरकार को विपक्षियों के साथ सम्मानपूर्ण रवैया अख्तियार करना चाहिए तथा आज इस चूक के लिए जिम्मेवार व्यक्ति को सबक सिखाना चाहिए।

POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–9 SEPT 2024 AMBERNATH PAGE 4 OF 4 RS 5/-

Miscellaneous

यह कैसा न्याय है, भाई !

कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक खंड ने एक लोकहित याचिका (PIL) दायर करने वाले पर 50000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए भविष्य में कभी भी PIL दायर करने पर रोक भी लगा दिया है ।

वकील स्वयं याचिकाकर्ता थे। उन्होंने लोक हित याचिका में मांग की थी कि कलकत्ता हाई कोर्ट की एक जज जस्टिस अमृता सिन्हा द्वारा सुनवाई किए जा रहे पुलिस की निष्क्रियता के एक मामले को अन्य जज के सुपुर्द कर दिया जाय क्योंकि जस्टिस सिन्हा के पति के खिलाफ पुलिस एक अन्य मामले में जज पत्नी का नाम लेकर जांच को प्रभावित करने के तथाकथित एक मामला की जांच कर रही है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि जस्टिस सिन्हा द्वारा पुलिस की निष्क्रियता के मामले की सुनवाई करने से न्याय में लोगों का विश्वास कम होगा।

मेरी समझ से इसमें कोई गलती नहीं दिखती है क्योंकि विधिशास्त के मुताबिक यह सिद्धांत है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते दिखना भी चाहिए।

पर कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इसे बहुत गंभीरता से लेते हुए वकील साहब को आड़े हाथों ले लिया तथा दंड का आदेश पारित कर दिया ये कहते हुए कि यह तो मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने जैसी बात हो गयो।

ये बात हजम होने जैसी नहीं लगती है !

How To Stop Nirbhayas From Happening

All Accused but one a minor) in Nirbhaya -1 were hanged - Yet the monstrous crime continues.

After Nirbhaya – 1 laws pertaining to rape were revamped and has been made more stringent . Yet the crime goes on with impunity.

All political parties should hang their head together and chalk out some effective programme of actions.

Here is what I wish to suggest to minimise if not eliminate the menace of madness :-

1. Increase the strength of police force
2. Educate police to take prompt action on complaint
3. Ensure regular patrolling through routes mostly vulnerable or lonely or discarded routes or places
4. Revamp the Intelligence Units
5. Surprise visits to police stations by higher police officers like SP, DSP, IG DIG or ministers and CM as per their convenience
6. Increase the number of courts
7. Increase the number of judges
8. Increase the infrsstructures in courts
9. Ensure instant justice within a month or so unlike the present position where cases are dragged on for months, years or even decades
10. Ensure quickest disposal of Appeals, review or revision petitions withine a months or so
11. Name and shame the persons found guilty finally,

दुर्लभ एकता

हमेशा एक दूसरे के कट्टर विरोधी होते हुए भी भारत के सत्तापक्ष तथा विपक्ष में दुर्लभ एकता या समरूपता भी कभी कभी दिखती है मसलन :-

1. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुमत से एससी के अंदर वर्गीकरण तथा क्रीमी लेयर को वैधता देने वाले फैसले के विरोध में सत्तापक्ष तथा विपक्ष एक साथ खड़ा दिखता है।
2. सुप्रीम कोर्ट तथा चुनाव आयोग के अपराध के अभियुक्तों को चुनाव से वंचित रखने के सुझावों को भी सत्तापक्ष तथा विपक्ष ने एकमत होकर खारिज कर दिया था।
3. भारत में न्यायिक विलंबों के लिए भी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को चिंता नहीं है।
4. हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम के प्रति भी सत्तापक्ष तथा विपक्ष की उदासीनता एक जैसी है।
5. बिहार में दर्जनों पुल बह गए पर इससे भी सत्तापक्ष तथा विपक्ष विचलित नहीं दिखा ।
6. प्राकृतिक आपदाओं में भी भारत का सत्तापक्ष तथा विपक्ष एक रहता है।
7. बंगलादेश में हुए उथलपुथल पर प्रतिक्रिया देने में भी भारत का सत्तापक्ष तथा विपक्ष एक है।
8. इसराइल द्वारा फिलिस्तीन में किए जा राज नरसंहार के बारे में ही सत्तापक्ष तथा विपक्ष में उदासीनता लगभग समान है।
9. रशियन यूक्रेन युद्ध के बारे में भी सतापक्ष तथा विपक्ष लगभग एक है।
10. म्यांमार को लेकर भी सत्तापक्ष तथा विपक्ष लगभग एक समान मौन रहते हैं।

Travesty Of Justice

Have you ever heard of charge sheets running into lakhs of pages , to be specific 69000 physical pages and over a lakh of digital pages and 493 witnesses. They do so to scare or confuse the judges and scuttle the justice . Can you say how many days it will take in going through such voluminous documents !

Manish Sisodia has been released on bail by the Apex Court which has made scathing remark against the functioning of investigating agencies and even against the High Courts and trial court's judges.

They keep people in jail as much as they can because they know that their cases will fall flat after trials begin.

They want to punish the people during process only

punishing some one before trial is the worst kind of punishment this govt has devised. Out of thousands of cases under PMLA hardly any conviction is visible .

They can understand the agony only when they will be put behind bars under the same draconian rules.

आस्था

मैने एक जगह अनजान ब्रह्म (बरम्ह) का मंदिर देखा है। किसी ने एक पीपल के पेड़ के नीचे लाल झंडा गाड़ दिया होगा।कुछ धूप अगरबती जला दिया होगा। ये तांता बढ़ता चला गया होगा। बाद में तो वहां सैकड़ों की तादाद में औरते वहां अपना कष्ट या शरीर से भूत भगाने के लिए आने लगीं, खेलाने लगीं (झूम झूम कर बालों को बिखेर कर) अनाप सनाप बोलते गाते। चारों तरफ खबर फैल गई कि अमुक जगह के ब्रह्म (बरम्ह) बाबा बड़े प्रभावशाली हैं। हर बीमारी दूर कर देते हैं।

ज्ञातव्य है कि बिहार तथा शायद यूपी में भी ये मान्यता है कि अगर कोई ब्राह्मण की हत्या करता है तो ब्राह्मण ब्रम्ह (बरम्ह) बन जाता है तथा हत्यारे के पूरे परिवार को ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत तकलीफ देता है । इससे बचने का उपाय बस ये होता है कि हत्यारा या उसके परिवार के लोग ब्रम्ह (बरम्ह) की मूर्ति स्थापित कर पूजा प्रार्थना करते हैं तथा उसकी आने वाली पीढ़ियां भी भय वश ये सिलसिला जारी रखती हैं।अब इसे क्या कहा जाए - आस्था ही न !

Printed, published and owned by Harishankar Upadhyay and printed and published at Flat 15B, Jeevan Jyot, Bhidewadi, Kansai Section, Ambernath (East), Dist Thane (Maharashtra), PIN 421501. Editor Harishankar Upadhyay, Mobile 9869435995